

श्री. ज. पी. नायक से.
दस्ता आज दि. 13-1-17
13/1/17
13/1/17

A 192-417

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - दो/2017 अपील

- (1) बूँदा पत्नि हरदास
 - (2) शीलावाई पुत्री भूरा
- सभी निवासी ग्राम खडेली
तहसील बदरवास
जिला शिवपुरी

APL
13.1.17
G.P. Nayak
Adv.

---अपीलांदूस

विरुद्ध

म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर, शिवपुरी

---रिस्पाण्डेन्ट

(अपील अंतर्गत धारा धारा 44, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,
1959 के अंतर्गत - श्रीमान अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,
ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 607/2012-13 अपील में पारित
आदेश दिनांक 30-11-2016 के विरुद्ध)

क०पृ०उ०-2

APL

APL

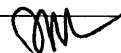
XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

अपील प्रकरण क्रमांक 192 -दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
16-1-17	<p>प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 607/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदकगण एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ आवेदकगण एवं शासन के पैनल लायर के के प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एवं निगरानी मेमो के तथ्यों अनुसार प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि आवेदकगण ने अनु0 जनजाति वर्ग का होने से उसके स्वामित्व की पिता से विरासत में प्राप्त ग्राम जारिया की भूमि सर्वे क्रमांक 559 एवं 569 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) को विक्रय करने का अनुमति आवेदन कलेक्टर शिवपुरी को प्रस्तुत किया, जिसे कलेक्टर जिला शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 88 / 2008-09 अ-21 में पारित आदेश दिनांक 6-9-11 से प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने प्रथम अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त न प्रकरण क्रमांक 607/2012-13 अपील में पारित</p>	





अपील प्र०क०१९२-दो/२०१७

आदेश दिनांक ३०-११-२०१६ से अपील निरस्त कर दी, इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

३/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि अभिलेख अनुसार वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के पिता स्वर्गीय भूरा नाम पर थी, जो भूरा के स्वर्गवास के बाद आवेदकगण के नाम नामांत्रित हुई है। यह भूमि आवेदकगण के पिता को ४०-४५ वर्ष पूर्व पट्टे पर प्राप्त हुई थी, जो विरासत में आवेदकगण को प्राप्त है, वर्तमान में नामान्तरण के द्वारा आवेदकगण के नाम चालू खसरे में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। विचार योग्य है कि क्या ऐसे भूमिस्वामी, जिसके पिता को वादग्रस्त भूमि ४०-५० वर्ष पूर्व पट्टे पर प्राप्त होना एवं आवेदकगण को विरासत में प्राप्त होना प्रमाणित है, भूमि विक्रय कर सकते हैं। ऐसे भूमिस्वामी को भूमि के प्रत्येक प्रकार के उपभोग के लिये स्वतंत्र माना गया है।

१. फुल्ला विरुद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य २०१२ रा०नि० २५६ (उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत है कि म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा १६५(७-ख) तथा १५८(३) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया- उपबंध आकर्षित नहीं होते। भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।
२. (१) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र० राज्य तथा अन्य एक २०१३ रा०नि० ८ (उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा १६५(७-ख) तथा १५८(३) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-उपबंध आकर्षित नहीं होते।





XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-ग्वालियर
 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
 अपील प्रकरण क्रमांक 192-दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
	<p>3. कैलाश तथा अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य 2005 रा0नि0 66 में व्यवस्था दी गई है कि आवंटन में प्राप्त की गई भूमि का विक्रय, आवंटन दिनांक से 10 वर्ष के भीतर नहीं किया जा सकता। इसका आशय यही है कि पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये 10 वर्ष निरन्तर खेती की गई, ऐसा पट्टाधारी 10 वर्ष उपरांत भूमिस्वामी होने से भूमि का विक्रय कर सकता है।</p> <p>स्पष्ट है कि आवेदकगण को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।</p> <p>3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 88/2008-09 अ-21 में पारित आदेश दिनांक 6-9-11 एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 607/12-13 अपील में पारित आदेश दि. 30-11-2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं आवेदकगण को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम जारिया की भूमि स.क्र. 559 एवं 569 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वादग्रस्त भूमि का क्रय-विक्रय इस आदेश के पारित होने के दिनांक से तीन माह के भीतर कराना अनिवार्य होगा - अन्यथा यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जावेगा। 2. वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र संपादित होने के दिन उप पंजीयक सत्यापन कर लेंगे कि क्रय-विक्रय धन की अदायगी वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित गाईड लायन के मान से एवं शासन के वर्तमान विक्रय नियमों के अधीन हो रहा है। 3. केता द्वारा विक्रय फल की राशि/अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके शासन के वर्तमान क्रय-विक्रय हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप अदा की जावेगी। 	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 सदस्य